भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 462

उत्तर देने की तारीख 28.11.2024

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना

462. डॉ. हेमन्त विष्णु सवरा:

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

श्री विजय बघेल:

श्री कृपानाथ मल्लाह:

श्री बसवराज बोम्मई:

श्री सुरेश कुमार कश्यप:

श्री जसवन्तसिंह सुमनभाई भाभोर:

श्री गणेश सिंह:

श्रीमती हिमाद्री सिंह:

श्रीमती कृति देवी देबबर्मन:

श्रीमती अपराजिता सारंगी:

श्री काली चरण सिंह:

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

श्री दर्शन सिंह चौधरी:

श्री मुकेश राजपूत:

श्री आशीष दुबे:

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

श्री खगेन मुर्मु:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोकतंत्र की जड़ों को उजागर करने वाली एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के लिए योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ईएमआरएस में छात्रों को संसद और ऐसी संस्थाओं के कामकाज से परिचित कराया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संसद और संसदीय संस्थाओं के कामकाज से जनजातीय छात्रों को परिचित कराने का महत्व और लाभ क्या है;

(घ) जनजातीय छात्रों को मुख्याधारा में लाने में ऐसे कार्यक्रम किस हद तक प्रभावी होने की संभावना है;

(ङ) उक्त ईएमआरएस विद्यालयों और उनमें विशेष रूप से झारखंड के चतरा जिले, महाराष्ट्र के पालघर जिले और राजस्थान में कार्यान्वित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त विद्यालयों के निर्माण में अब तक कुल कितना व्यय हुआ है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) ईएमआरएस योजना के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में कितने विद्यालय संचालित, स्वीकृत, निर्माणाधीन और प्रस्तावित हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके):

(क): वर्ष 2018-19 में जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। नई योजना के तहत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया, प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस, जिसमें 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्ति (जनगणना 2011 के अनुसार) हैं। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत शुरू में 288 ईएमआरएस विद्यालयों को वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अजजा छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आज तक, 715 विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 476 ईएमआरएस पूरे देश में कार्यरत की सूचना दी गई है, जिनसे लगभग 1,33,929 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) की स्थापना जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई है, जो ईएमआरएस की केंद्रीय क्षेत्र योजना का प्रबंधन और कार्यान्वयन करती है।

(ख से घ). मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के छात्रों को संसद और संसदीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली से परिचित कराने के महत्व को पहचाना है। इस पहल के हिस्से के रूप में, वर्ष 2024 में ईएमआरएस के लिए युवा संसद की योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को संसदीय प्रक्रियाओं का अनुकरण करने के लिए एक मंच प्रदान करना है, जिससे उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासन को समझने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

इसके अलावा, ईएमआरएस के छात्रों ने ऑनलाइन युवा संसद योजना में भी भाग लिया है, जिसने उन्हें वर्चुअल प्रारूप में संसदीय कार्यवाही से जुड़ने में सक्षम बनाया है। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि भौगोलिक बाधाओं के बावजूद वे संसद से जुडे रहे और संसद के कामकाज के बारे में सूचना प्राप्त करते रहे।

इसके अलावा, ईएमआरएस में वाई20 की एक योजना भी शुरू की गई थी। इस पहल को जी20 ढांचे के एक प्रोटोटाइप के रूप में तैयार (डिजाइन) किया गया है, जिससे छात्रों को वैश्विक चर्चाओं में शामिल होने और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सहयोग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलेगा।

इसके अलावा, ईएमआरएस के छात्रों को पुराने और नए दोनों संसद सदनों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया। इन दौरों ने उन्हें भारतीय संसद के संचालन और महत्व को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने का अवसर दिया है।

(ङ) केंद्रीय बजट 2021 में बजट घोषणा के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में ईएमआरएस की निर्माण लागत मौजूदा 20.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 38.00 करोड़ रुपये और पहाड़ी, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 24.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 48.00 करोड़ रुपये कर दी गई है। इन विद्यालयों को चलाने के लिए अनुमोदित आवर्ती लागत प्रति छात्र प्रति वर्ष 1,09,000 रुपये है। चतरा जिला, झारखंड, पालघर जिला, महाराष्ट्र और राजस्थान में ईएमआरएस की वर्तमान स्थिति **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(च) हिमाचल प्रदेश सहित ईएमआरएस की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **अनुलग्नक II** में दी गई है।

अनुलग्नक-I

"एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना" के संबंध में डॉ. हेमन्त विष्णु सवरा: श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे, श्री विजय बघेल, श्री कृपानाथ मल्लाह, श्री बसवराज बोम्मई, श्री सुरेश कुमार कश्यप, श्री जसवन्तसिंह सुमनभाई भाभोर, श्री गणेश सिंह, श्रीमती हिमाद्रि सिंह, श्रीमती कृति देवी देबबर्मन, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्री काली चरण सिंह, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री दर्शन सिंह चौधरी, श्री मुकेश राजपूत, श्री आशीष दुबे, श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया, श्री खगेन मुर्मु द्वारा दिनांक 28.11.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 462 के भाग (ङ) के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक

चतरा जिला, झारखंड, पालघर जिला, महाराष्ट्र और राजस्थान में ईएमआरएस की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	राज्य	जिला	ब्लॉक/तालुका	स्थान स्वीकृति वर्ष	कार्यात्मक स्थिति	निर्माण स्थिति
1	झारखंड	चतरा	कान्हाचट्टी	2014-15	कार्यात्मक	पूर्ण
2	महाराष्ट्र	पालघर	दहानु	2020-21	कार्यात्मक	प्रगति में
3	महाराष्ट्र	पालघर	जवाहर	2018-19	कार्यात्मक	निर्माण-पूर्व चरण
4	महाराष्ट्र	पालघर	मोखाडा	2021-22	कार्यात्मक	निर्माण-पूर्व चरण
5	महाराष्ट्र	पालघर	पालघर	1997-98	कार्यात्मक	पूर्ण
6	महाराष्ट्र	पालघर	तलासरी	2018-19	कार्यात्मक	प्रगति में
7	महाराष्ट्र	पालघर	वड़ा	2024-25	कार्यात्मक	निर्माण-पूर्व चरण
8	महाराष्ट्र	पालघर	विक्रमगढ़	2024-25	गैर-कार्यात्मक	निर्माण-पूर्व चरण
9	राजस्थान	अलवर	राजगढ़	2010-11	गैर-कार्यात्मक	पूर्ण
10	राजस्थान	अलवर	रेनी	2011-12	कार्यात्मक	पूर्ण
11	राजस्थान	बांसवाड़ा	आनंदपुरी	2010-11	कार्यात्मक	पूर्ण
12	राजस्थान	बांसवाड़ा	आनंदपुरी	2013-14	कार्यात्मक	पूर्ण
13	राजस्थान	बांसवाड़ा	बागीदौरा	2020-21	कार्यात्मक	पूर्ण
14	राजस्थान	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	2018-19	कार्यात्मक	पूर्ण
15	राजस्थान	बांसवाड़ा	गढ़ी	2020-21	कार्यात्मक	पूर्ण
16	राजस्थान	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	1997-98	कार्यात्मक	पूर्ण
17	राजस्थान	बारां	शाहबाद	1997-98	कार्यात्मक	पूर्ण
18	राजस्थान	डूंगरपुर	डूंगरपुर	2019-20	कार्यात्मक	पूर्ण
19	राजस्थान	डूंगरपुर	सबला	2010-11	कार्यात्मक	पूर्ण
20	राजस्थान	डूंगरपुर	सागबारा	2020-21	कार्यात्मक	प्रगति में
21	राजस्थान	डूंगरपुर	सीमलवाड़ा	1998-99	कार्यात्मक	पूर्ण
22	राजस्थान	जयपुर	बस्सी	2010-11	कार्यात्मक	पूर्ण
23	राजस्थान	जयपुर	जामवा रामगढ	2016-17	कार्यात्मक	प्रगति में
24	राजस्थान	करौली	टोडाभीम	2010-11	गैर-कार्यात्मक	पूर्ण

25	राजस्थान	प्रतापगढ़	अरनोद	2020-21	कार्यात्मक	प्रगति में
26	राजस्थान	प्रतापगढ़	धरियावद	2020-21	कार्यात्मक	पूर्ण
27	राजस्थान	प्रतापगढ़	पीपलखूंट	2018-19	कार्यात्मक	पूर्ण
28	राजस्थान	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	2007-08	कार्यात्मक	पूर्ण
29	राजस्थान	सवाई माधोपुर	बामनवास	2010-11	कार्यात्मक	पूर्ण
30	राजस्थान	सिरोही	आबूरोड	1997-98	कार्यात्मक	पूर्ण
31	राजस्थान	टोंक	निवाई	1999-00	कार्यात्मक	पूर्ण
32	राजस्थान	उदयपुर	गोगुंदा	2013-14	कार्यात्मक	पूर्ण
33	राजस्थान	उदयपुर	झाड़ोल	2020-21	कार्यात्मक	पूर्ण
34	राजस्थान	उदयपुर	खेरवाड़ा	2021-22	कार्यात्मक	प्रगति में
35	राजस्थान	उदयपुर	कोट्रा	1997-98	कार्यात्मक	पूर्ण
36	राजस्थान	उदयपुर	लसाडिया	2020-21	कार्यात्मक	पूर्ण
37	राजस्थान	उदयपुर	ऋषभदेव	1999-00	कार्यात्मक	पूर्ण
38	राजस्थान	उदयपुर	सलूंबर	2020-21	कार्यात्मक	पूर्ण
39	राजस्थान	उदयपुर	शारदा	2019-20	कार्यात्मक	पूर्ण

"एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना" के संबंध में डॉ. हेमन्त विष्णु सवराः श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे, श्री विजय बघेल, श्री कृपानाथ मल्लाह, श्री बसवराज बोम्मई, श्री सुरेश कुमार कश्यप, श्री जसवन्तसिंह सुमनभाई भाभोर, श्री गणेश सिंह, श्रीमती हिमाद्रि सिंह, श्रीमती कृति देवी देबबर्मन, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्री काली चरण सिंह, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री दर्शन सिंह चौधरी, श्री मुकेश राजपूत, श्री आशीष दुबे, श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया, श्री खगेन मुर्मु द्वारा दिनांक 28.11.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 462 के भाग (च) के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक

ईएमआरएस की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत विद्यालय	स्वीकृत स्थान	कार्यात्मक ईएमआरएस	ईएमआरएस की भवन स्थिति		
					पूर्ण	निर्माणाधीन	निर्माण-पूर्व चरण
1	आंध्र प्रदेश	28	28	28	21	6	1
2	अरुणाचल प्रदेश	11	10	5	7	1	2
3	असम	17	16	1	2	9	5
4	बिहार	3	3	2	1	2	
5	छत्तीसगढ़	75	75	74	31	21	23
6	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1	1	1	0	1	
7	गुजरात	47	47	38	25	10	12
8	हिमाचल प्रदेश	4	4	4	1	0	3
9	जम्मू एवं कश्मीर	6	6	6	2	3	1
10	झारखंड	91	89	51	39	38	12
11	कर्नाटक	12	12	12	12	0	
12	केरल	4	4	4	2	1	1
13	लद्दाख	3	3		0	0	3
14	मध्य प्रदेश	71	71	63	42	22	7
15	महाराष्ट्र	39	39	37	15	17	7
16	मणिपुर	21	21	3	4	10	7
17	मेघालय	38	36		1	14	21
18	मिजोरम	17	17	11	8	3	6
19	नागालैंड	22	22	3	3	19	
20	ओडिशा	114	108	47	48	43	17
21	राजस्थान	31	31	30	27	4	
22	सिक्किम	4	4	4	4	0	
23	तमिलनाडु	8	8	8	7	0	1
24	तेलंगाना	23	23	23	18	5	
25	त्रिपुरा	21	21	6	6	13	2
26	उत्तर प्रदेश	4	4	3	4	0	
27	उत्तराखंड	4	4	4	2	2	
28	पश्चिम बंगाल	9	8	8	7	0	1
	कुल	728	715	476	339	244	132